

प्रजा प्राथमिक पार्टी का संविधान

भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण हेतु अंगीकृत

Praja Prathamik Party · पीपल्स प्राइमरी पार्टी (पीपीपी)

प्रस्तावना

हम, भारत के नागरिक, इस पार्टी का गठन एक सर्वोपरि उद्देश्य के साथ करते हैं — भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना — और सार्वजनिक जीवन को एक ऐसी व्यवस्था के माध्यम से नया रूप देना, जिसमें साधारण सदस्य पार्टी के उम्मीदवार चुनते हैं, पद चाहने वाले उसे खुली प्रतिस्पर्धा से अर्जित करते हैं, और भारत के सबसे निपुण नागरिकों का अनुभव पार्टी का मार्गदर्शन करता है, उस पर शासन नहीं। इस पार्टी में चुनाव लड़ने का टिकट कभी बेचा नहीं जाता: वह सदस्यों के मत जीतकर अर्जित किया जाता है। पार्टी रचनात्मक, मुद्दा-आधारित राजनीति करेगी: वह भारत के विकास में सहायक हर उपाय का समर्थन करेगी, चाहे उसे कोई भी दल प्रस्तावित करे।

पार्टी तीन स्तरों में संगठित है:

1. **सदस्य (स्तर 1):** साधारण और सशुल्क सदस्य, जो पार्टी का आधार हैं और उसके उम्मीदवार चुनते हैं।
2. **कार्यकारी सदस्य (स्तर 2):** वे सशुल्क सदस्य जिन्होंने प्रकाशित, वस्तुनिष्ठ मानदंड पूरे किए हैं, जो पार्टी संगठन का संचालन करते हैं और केवल वही उसके प्राथमिक चुनाव (प्राइमरी) लड़ सकते हैं।
3. **सलाहकार परिषदें (स्तर 3):** प्रतिष्ठित नागरिकों की एक केंद्रीय सलाहकार परिषद और राज्य सलाहकार परिषदें, जो पार्टी को सलाह देती हैं और प्रकाशित मानदंडों के आधार पर तय करती हैं कि कौन कार्यकारी सदस्य बन सकता है और कौन प्राइमरी में भाग ले सकता है। सलाहकार परिषद के सदस्य न कभी कार्यकारी पद धारण करते हैं, न चुनाव लड़ते हैं।

भाग I: नाम, कार्यालय, उद्देश्य और परिभाषाएँ

अनुच्छेद 1. नाम। पार्टी का नाम हिंदी में प्रजा प्राथमिक पार्टी और अंग्रेज़ी में People's Primary Party होगा, जिसका संक्षिप्त रूप दोनों भाषाओं में पीपीपी (PPP) होगा।

अनुच्छेद 2. मुख्य कार्यालय। पार्टी का मुख्य कार्यालय [पूरा पता] पर होगा। पते में किसी भी परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

अनुच्छेद 3. संविधान के प्रति निष्ठा। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगी, और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगी।

अनुच्छेद 4. उद्देश्य। पार्टी के उद्देश्य हैं:

1. अपने सदस्यों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के माध्यम से संसद, राज्य विधानमंडलों और स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ना;

2. नियमित, गुप्त मतदान वाले चुनावों और प्रकाशित नियमों के माध्यम से आंतरिक लोकतंत्र का पालन करना;
3. भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, जो पार्टी का सर्वोपरि उद्देश्य है; जाति-आधारित आरक्षण के स्थान पर आर्थिक आवश्यकता पर आधारित आरक्षण लाना; और स्वतंत्रता की शताब्दी, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस हेतु:
 1. पार्टी के अपने आचरण से शुरुआत करते हुए, पार्टी टिकटों की बिक्री और चुनावों में बेहिसाबी धन के प्रयोग को समाप्त करना;
 2. लोकपाल और लोकायुक्तों को सशक्त बनाना, व्हिसल-ब्लोअरों की रक्षा करना, और भ्रष्टाचार के मामलों की समयबद्ध जाँच और सुनवाई सुनिश्चित करना;
 3. सरकारी सेवाओं, भुगतानों, लाइसेंसें और सार्वजनिक खरीद को डिजिटल, पारदर्शी और विवेकाधीन देरी से मुक्त बनाना;
 4. पुलिस और न्याय व्यवस्था में सुधार करना ताकि न्याय शीघ्र, निष्पक्ष और सस्ता हो;
 5. प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करना;
 6. आर्थिक विकास, रोज़गार, उद्यमिता, विनिर्माण, कृषि, विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना;
 7. पर्यावरण की रक्षा करते हुए आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना; और
 8. संविधान और कानूनों में विधिसम्मत संशोधन के माध्यम से इस हेतु कार्य करना कि शिक्षा, सार्वजनिक रोज़गार और कल्याण में आरक्षण जाति के बजाय आर्थिक आवश्यकता पर आधारित हो, और महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और गरीबों का विशेष ध्यान रखते हुए प्रत्येक नागरिक के लिए समान अवसर और गरिमा सुनिश्चित करना;
4. अपने उद्देश्यों को केवल विधिसम्मत, शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों से प्राप्त करना।

अनुच्छेद 4क. मुद्दा-आधारित राजनीति।

1. पार्टी किसी भी सरकार या राजनीतिक दल की प्रत्येक नीति, विधेयक, बजट और कार्रवाई को उसके गुण-दोष के आधार पर, अनुच्छेद 4 के उद्देश्यों की कसौटी पर परखेगी, न कि इस आधार पर कि उसे किस दल ने प्रस्तावित किया है।
2. पार्टी, उसके पदाधिकारी और उसके निर्वाचित प्रतिनिधि भ्रष्टाचार-मुक्त शासन या भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाले हर उपाय का, मत द्वारा और सार्वजनिक रूप से, समर्थन करेंगे, चाहे उसे कोई भी दल या सरकार प्रस्तावित करे।
3. पार्टी किसी उपाय का विरोध केवल इसलिए नहीं करेगी कि उसे किसी अन्य दल ने प्रस्तावित किया है, और न ही दलीय लाभ के लिए संसद, राज्य विधानमंडल या स्थानीय निकाय की कार्यवाही में बाधा डालेगी।
4. जहाँ पार्टी किसी उपाय का विरोध करती है, वहाँ वह अपने कारण प्रकाशित करेगी और, जहाँ तक संभव हो, एक रचनात्मक विकल्प प्रस्तावित करेगी।
5. पार्टी नीतियों और आचरण की आलोचना करेगी, व्यक्तियों की नहीं, और अन्य दलों के सदस्यों पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगी।
6. राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद वर्ष में कम से कम एक बार उन उपायों का अभिलेख, कारणों सहित, प्रकाशित करेगी जिनका पार्टी ने अन्य दलों और सरकारों के प्रस्तावों में समर्थन या विरोध किया है।

अनुच्छेद 5. ध्वज और प्रतीक। पार्टी का ध्वज सफ़ेद होगा, जिसके मध्य में गहरे नीले रंग में पार्टी का प्रतीक और उसके नीचे हिंदी और अंग्रेज़ी में पार्टी का नाम होगा। पार्टी निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन, अपने सामान्य चुनाव चिह्न के रूप में तराजू के लिए, और दूसरी वरीयता के रूप में मतपेटी के लिए, निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगी।

अनुच्छेद 6. इस संविधान की स्थिति। यह संविधान पार्टी के प्रत्येक सदस्य, पदाधिकारी और परिषद पर बाध्यकारी है। इससे असंगत कोई भी नियम, संकल्प या निर्णय असंगति की सीमा तक शून्य है। अनुसूचियाँ इस संविधान का भाग हैं।

अनुच्छेद 7. परिभाषाएँ। इस संविधान में:

1. “सदस्य” का अर्थ भाग II के अधीन साधारण सदस्य या सशुल्क सदस्य है;
2. “कार्यकारी सदस्य” का अर्थ भाग III के अधीन स्तर 2 में प्रवेश पाया सशुल्क सदस्य है;
3. “केंद्रीय सलाहकार परिषद” और “राज्य सलाहकार परिषद” का अर्थ भाग IV के अधीन गठित परिषदें हैं, और “सलाहकार परिषद” का अर्थ इनमें से कोई भी है;
4. “पात्रता मानदंड” का अर्थ अनुसूची I के मानदंड हैं, और “निरहकारी अपराध” का अर्थ अनुसूची II में सूचीबद्ध अपराध है;
5. “प्राइमरी” (प्राथमिक चुनाव) का अर्थ किसी सार्वजनिक चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार चुनने हेतु सदस्यों के बीच होने वाला चुनाव है;
6. “दावेदार” का अर्थ प्राइमरी लड़ने का इच्छुक कार्यकारी सदस्य है;
7. “निर्वाचन प्राधिकरण” और “मध्यस्थता अधिकरण” का अर्थ भाग VII के अधीन गठित निकाय हैं;
8. “राज्य” में विधानमंडल वाला संघ राज्यक्षेत्र सम्मिलित है।

भाग II: स्तर 1 – सदस्य

अनुच्छेद 8. पात्रता और सदस्यता के वर्ग। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या अधिक है और जिसका नाम भारत में किसी निर्वाचक नामावली में है, सदस्य बन सकता है, बशर्ते वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य न हो और इस संविधान तथा अनुसूची III की आचार संहिता को लिखित रूप में स्वीकार करे। सदस्यता के दो वर्ग हैं:

1. साधारण सदस्य, जो कोई शुल्क नहीं देते; और
2. सशुल्क सदस्य, जो ₹100 का वार्षिक सदस्यता शुल्क देते हैं, जिसे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद वर्ष में एक बार संशोधित कर सकती है।

अनुच्छेद 8क. अनिवासी भारतीय और भारत के प्रवासी नागरिक।

1. विदेश में रहने वाला भारत का नागरिक (अनिवासी भारतीय) साधारण सदस्य बन सकता है।
2. भारत का प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारक प्रवासी सहयोगी के रूप में साधारण सदस्य बन सकता है। प्रवासी सहयोगी कोई शुल्क (अनुच्छेद 10क के अधीन अंशदान सहित) नहीं देते और पार्टी को कोई दान नहीं देते, निर्वाचन आयोग में पंजीकरण हेतु आवश्यक सदस्यों में उनकी गिनती नहीं होती, और वे ऐसी किसी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे जो कानून भारत के प्रवासी नागरिकों के लिए निषिद्ध करता है।
3. अनिवासी भारतीय और प्रवासी सहयोगी किसी प्राइमरी या आंतरिक चुनाव में मत नहीं देंगे, न सशुल्क सदस्य या कार्यकारी सदस्य बनेंगे, न पार्टी पद धारण करेंगे, न पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
4. अनिवासी भारतीय और प्रवासी सहयोगी अनुच्छेद 22 की सीमा के भीतर सलाहकार परिषद में सेवा कर सकते हैं। परिषद में वे सलाह देने में और अनुच्छेद 24(2) के अधीन कार्यकारी सदस्यों के प्रवेश संबंधी निर्णयों में भाग लेते हैं, और अन्य सभी प्रमाणन निर्णयों से स्वयं को अलग रखते हैं।

5. यदि भारत के प्रवासी नागरिकों या विदेशी अंशदान से संबंधित कानून में परिवर्तन होता है, तो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद पार्टी को कानून के भीतर रखने के लिए इस अनुच्छेद में आवश्यक संशोधन करेगी।

अनुच्छेद 9. पंजीकरण और सत्यापन। प्रत्येक आवेदन, चाहे ऑनलाइन हो या कागज़ पर, सदस्यता देने से पहले आवेदक की निर्वाचक नामावली प्रविष्टि से सत्यापित किया जाएगा। निर्वाचन प्राधिकरण राज्य, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित सदस्यों का एक एकल डिजिटल रजिस्टर रखेगा। सदस्यों के व्यक्तिगत डेटा को उनकी सहमति से और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार संभाला जाएगा।

अनुच्छेद 9क. सदस्यों का सार्वजनिक रजिस्टर।

1. पार्टी अपनी वेबसाइट पर सभी कार्यकारी सदस्यों, पदाधिकारियों, सलाहकार परिषद सदस्यों, दावेदारों और उम्मीदवारों के नाम और निर्वाचन क्षेत्र प्रकाशित करेगी और उन्हें अद्यतन रखेगी।
2. पार्टी अन्य सभी सदस्यों के नाम और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भी, सदस्यता के समय दी गई उनकी सहमति से, प्रकाशित करेगी। कोई सदस्य व्यक्तिगत सुरक्षा, रोज़गार या निजता के कारणों से निर्वाचन प्राधिकरण से अपना नाम न दिखाने का अनुरोध कर सकता है; तब वह केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र की गणना में दिखाया जाता है।
3. प्रत्येक प्राइमरी से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सदस्यों की संख्या, और प्रत्येक प्राइमरी में मत देने के पात्र सदस्यों की संख्या, प्रकाशित की जाएगी।
4. किसी भी सदस्य का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता, पहचान संख्या या अन्य संपर्क विवरण प्रकाशित नहीं किया जाएगा। रजिस्टर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुसार रखा जाएगा।

अनुच्छेद 10. वर्ग के अनुसार अधिकार। साधारण और सशुल्क दोनों प्रकार के सदस्य, अनुच्छेद 12 के अधीन, प्राइमरी और आंतरिक चुनावों में मत दे सकते हैं। केवल वह सशुल्क सदस्य जिसने कम से कम एक वर्ष तक लगातार सशुल्क सदस्यता रखी हो, कार्यकारी सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है। साधारण सदस्य कभी भी सशुल्क सदस्य बन सकता है; एक वर्ष की अवधि पहला शुल्क देने की तिथि से गिनी जाती है।

अनुच्छेद 10क. कार्य-अंशदान।

1. प्रत्येक कार्यकारी सदस्य पार्टी के संचालन व्यय के लिए ₹1,000 प्रति माह का अंशदान देगा; इसमें अनुच्छेद 8 के अधीन सशुल्क सदस्यता शुल्क सम्मिलित है। प्रत्येक सलाहकार परिषद सदस्य ₹1,00,000 प्रति वर्ष का अंशदान देगा, सिवाय भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के, जो अनुच्छेद 8क के अधीन कुछ नहीं देता।
2. सभी अंशदान एक कार्य-निधि में जमा होते हैं, जिसका उपयोग केवल पार्टी के संगठनात्मक व्यय के लिए होता है: कार्यालय और कर्मचारी, ऑनलाइन सदस्यता, मतदान और सत्यापन प्रणालियाँ, प्रशिक्षण, लेखापरीक्षा, और निर्वाचन प्राधिकरण, मध्यस्थता अधिकरण, सत्यनिष्ठा आयोग तथा सदस्य ओम्बड्समैन का व्यय। कार्य-निधि किसी व्यक्ति के प्राइमरी या चुनाव अभियान पर खर्च नहीं की जाएगी।
3. अंशदान प्रत्येक कार्यकारी सदस्य के लिए समान है, चाहे वह चुनाव लड़ना चाहे या नहीं। इससे प्रमाणन, नामांकन या उम्मीदवारी का कोई अधिकार नहीं मिलता, और पार्टी में कोई लाभ पाने के लिए कोई भी अंशदान से अधिक भुगतान नहीं कर सकता; कोई भी अतिरिक्त भुगतान अनुच्छेद 47 के अधीन दान है।
4. जो कार्यकारी सदस्य विद्यार्थी है, बेरोज़गार है, या जिसकी पारिवारिक आय ₹3,00,000 प्रति वर्ष से कम है, वह इसके बजाय ₹100 प्रति माह, या प्रति माह दस घंटे की सत्यापित पार्टी सेवा, का

अंशदान दे सकता है। निर्वाचन प्राधिकरण गोपनीय स्व-घोषणा के आधार पर निर्णय करता है; यह निर्णय किसी सलाहकार परिषद को नहीं बताया जाता और किसी प्रमाणन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती।

5. राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद प्रति वर्ष अंशदान इस प्रकार तय करेगी कि वे बजटीय संचालन व्यय से अधिक न हों, और कोई भी अधिशेष अगले वर्ष के अंशदान को घटाएगा। अंशदान दो-तिहाई मत से वर्ष में एक बार संशोधित किए जा सकते हैं।
6. सभी अंशदान भुगतानकर्ता के अपने नाम से बैंकिंग माध्यमों द्वारा दिए जाएंगे, उनकी रसीद दी जाएगी, और उनका हिसाब अनुच्छेद 47 और 47क के अधीन रखा और प्रकाशित किया जाएगा।
7. जो सलाहकार परिषद सदस्य देय तिथि के 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करता, उसका स्थान रिक्त हो जाता है।

अनुच्छेद 11. सभी सदस्यों के अधिकार। अच्छी स्थिति वाले प्रत्येक सदस्य को अधिकार है:

1. अनुच्छेद 12 के अधीन, अपने लोक सभा और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की प्राइमरी में मत देने का;
2. इस संविधान के अनुसार पार्टी निकायों के चुनावों में मत देने का;
3. पार्टी के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे और सलाहकार परिषदों के वार्षिक प्रमाणन प्रतिवेदन प्राप्त करने का;
4. अपनी राज्य कार्यकारी परिषद को नीतिगत प्रस्ताव भेजने का; और
5. किसी भी अनुशासनात्मक निर्णय के विरुद्ध मध्यस्थता अधिकरण में अपील करने का।

अनुच्छेद 12. प्राइमरी में मत देने की शर्तें। कोई सदस्य प्राइमरी में तभी मत दे सकता है जब वह:

1. प्राइमरी अधिसूचित होने की तिथि से कम से कम 12 महीने पहले से अच्छी स्थिति वाला सदस्य हो और, सशुल्क सदस्य होने की दशा में, उसका शुल्क अद्यतन जमा हो;
2. भारत में सामान्यतः निवास करने वाला भारत का नागरिक हो और उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हो;
3. अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या कानून द्वारा अनुमत किसी अन्य विधि से, निर्वाचन प्राधिकरण की प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन मतदान हेतु अपनी पहचान सत्यापित कर चुका हो;
4. इस संविधान, आचार संहिता और प्राइमरी की प्रक्रिया पर पार्टी का संक्षिप्त ऑनलाइन परिचय-पाठ्यक्रम एक बार पूरा कर चुका हो; और
5. अनिवासी भारतीय, प्रवासी सहयोगी या किसी सलाहकार परिषद का सदस्य न हो।

यही शर्तें, यथास्थिति राज्य या देश के लिए, प्रत्येक अन्य आंतरिक चुनाव पर लागू होती हैं।

अनुच्छेद 13. सदस्यता की समाप्ति। सदस्यता त्यागपत्र देने पर, किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने पर, या भाग VIII के अधीन निष्कासन पर समाप्त होती है। जो सशुल्क सदस्य सूचना के 6 महीने के भीतर नवीनीकरण नहीं करता, वह साधारण सदस्य बन जाता है और कार्यकारी सदस्य नहीं रहता।

भाग III: स्तर 2 – कार्यकारी सदस्य और कार्यकारी परिषदें

अनुच्छेद 14. भूमिका। कार्यकारी सदस्य पार्टी का कार्यकारी संगठन बनाते हैं। केवल कार्यकारी सदस्य ही पार्टी पद धारण कर सकते हैं या प्राइमरी लड़ सकते हैं।

अनुच्छेद 15. प्रवेश। कोई सशुल्क सदस्य केवल उस राज्य की राज्य सलाहकार परिषद के अनुच्छेद 25 के अधीन प्रमाणन पर कार्यकारी सदस्य बनता है, जिसमें वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है। प्रमाणन केवल तभी दिया जा सकता है जब आवेदक अनुसूची I के भाग क का प्रत्येक मानदंड पूरा करे, और वह अनुच्छेद 25(3) के अधीन सलाहकार परिषद के निर्णय के अधीन रहता है।

अनुच्छेद 16. निरंतर पात्रता। कार्यकारी सदस्य अपनी सदस्यता के दौरान भाग क के मानदंड पूरे करता रहेगा, अपनी शपथपूर्वक घोषणा प्रति वर्ष और किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के 30 दिनों के भीतर अद्यतन करेगा, और सशुल्क सदस्य बना रहेगा तथा अनुच्छेद 10क के अधीन मासिक अंशदान जमा करता रहेगा; तीन महीने का बकाया होने पर कार्यकारी सदस्यता समाप्त हो जाती है। जो कार्यकारी सदस्य किसी मानदंड को पूरा करना बंद कर देता है, वह अपील के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 25 के अधीन राज्य सलाहकार परिषद के निष्कर्ष पर कार्यकारी सदस्य नहीं रहता।

अनुच्छेद 17. राज्य कार्यकारी परिषदें। किसी राज्य में पंजीकृत सभी कार्यकारी सदस्य उस राज्य की राज्य कार्यकारी परिषद बनाते हैं। राज्य कार्यकारी परिषद:

1. अनुच्छेद 40 के अधीन राज्य पदाधिकारियों का चुनाव करेगी;
2. उस राज्य में पार्टी का संगठन, अभियान और सदस्यता अभियान चलाएगी;
3. इस संविधान के अनुरूप ज़िला और निर्वाचन क्षेत्र इकाइयों के नियम बनाएगी; और
4. व्यक्तिगत रूप से या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, अपने सदस्यों के पाँचवें भाग की गणपूर्ति के साथ, वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।

अनुच्छेद 18. राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद पार्टी का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें सम्मिलित हैं:

1. राष्ट्रीय पदाधिकारी;
2. प्रत्येक राज्य कार्यकारी परिषद द्वारा गुप्त मतदान से चुने गए प्रतिनिधि, उस राज्य के प्रत्येक 500 कार्यकारी सदस्यों पर एक प्रतिनिधि की दर से, तथा राज्य कार्यकारी परिषद वाले प्रत्येक राज्य से कम से कम दो प्रतिनिधि; और
3. लोक सभा और प्रत्येक राज्य विधान सभा में पार्टी के नेता, मताधिकार-रहित सदस्यों के रूप में।

इसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी, जिसकी गणपूर्ति मताधिकार-प्राप्त सदस्यों का एक-तिहाई होगी। जब तक यह संविधान अन्यथा अपेक्षित न करे, निर्णय उपस्थित और मत देने वालों के साधारण बहुमत से होते हैं।

अनुच्छेद 18क. वार्षिक सदस्य सम्मेलन। पार्टी प्रति वर्ष व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन, सदस्यों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद वर्ष के कार्य और लेखापरीक्षित लेखों पर प्रतिवेदन देगी, वार्षिक नीति मतदान के परिणाम घोषित किए जाएंगे, और प्रत्येक सदस्य उपस्थित होकर प्रश्न पूछ सकता है।

अनुच्छेद 19. दायित्व। कार्यकारी सदस्य आचार संहिता का पालन करेंगे, किसी भी हित-संघर्ष की घोषणा करेंगे, अपने द्वारा लड़ी गई किसी भी प्राइमरी का परिणाम मानेंगे, और पार्टी के चुने हुए उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।

अनुच्छेद 20. स्तर छोड़ना। कार्यकारी सदस्य अपनी सदस्यता समाप्त किए बिना किसी भी समय कार्यकारी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है।

भाग IV: स्तर 3 – सलाहकार परिषदें

अनुच्छेद 21. केंद्रीय सलाहकार परिषद। केंद्रीय सलाहकार परिषद में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले 21 व्यक्तियों की निश्चित सदस्यता होती है, जो उद्योग, वाणिज्य और वित्त; विज्ञान और चिकित्सा; विधि और लोक सेवा; एक से अधिक धर्मों के प्रतिनिधित्व सहित धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन; परोपकार; तथा कला, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन से लिए जाते हैं।

अनुच्छेद 22. राज्य सलाहकार परिषदें। किसी राज्य में पार्टी के कम से कम 10,000 सदस्य हो जाने पर उस राज्य के लिए, उस राज्य में प्रतिष्ठा रखने वाले और उन्हीं क्षेत्रों से लिए गए 21 सदस्यों की एक राज्य सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। वह कम से कम 11 सदस्यों के साथ शुरू हो सकती है और उपयुक्त आवेदक मिलने पर 21 सदस्यों तक बढ़ सकती है। राज्य सलाहकार परिषद गठित होने तक केंद्रीय सलाहकार परिषद उस राज्य के लिए उसके कार्य करती है। प्रत्येक सलाहकार परिषद के कम से कम तीन-चौथाई सदस्य, और उसका अध्यक्ष, भारत में सामान्यतः निवास करने वाले भारत के नागरिक होंगे; शेष, अनुच्छेद 8क के अधीन, अनिवासी भारतीय या भारत के प्रवासी नागरिक हो सकते हैं।

अनुच्छेद 23. नियुक्ति और कार्यकाल।

1. केंद्रीय सलाहकार परिषद के पहले 21 सदस्य, अनुच्छेद 21, 22, 26 और 27 के अधीन रहते हुए, पंजीकरण के छह महीनों के भीतर पार्टी के संस्थापक, [संस्थापक का नाम], द्वारा चुने जाते हैं: सात छह वर्ष के कार्यकाल के लिए, सात चार वर्ष के लिए और सात दो वर्ष के लिए; प्रत्येक का कार्यकाल सार्वजनिक रूप से निकाली गई लॉटरी द्वारा तय होगा।
2. पहले कार्यकालों के बाद, सलाहकार परिषद का प्रत्येक सदस्य छह वर्ष के लिए नियुक्त होता है, और प्रत्येक सलाहकार परिषद की एक-तिहाई सीटें प्रत्येक दो वर्ष में रिक्त होती हैं।
3. उसके बाद, सीटें आवेदनों से भरी जाती हैं। निर्वाचन प्राधिकरण सीटें रिक्त होने से कम से कम 90 दिन पहले सार्वजनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदक अनुच्छेद 21 में सूचीबद्ध किसी क्षेत्र का प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, अनुसूची I के भाग क के मानदंड 4 से 8 और 11 पूरे करने चाहिए, और पिछले 12 महीनों में कार्यकारी सदस्य या पार्टी पदधारी नहीं रहा होना चाहिए।
4. केंद्रीय सलाहकार परिषद की सीटें पात्र आवेदकों में से एक नामांकन समिति (राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा गुप्त मतदान से चुने गए उसके तीन सदस्य) द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई मत से अनुसमर्थन के अधीन, भरी जाती हैं।
5. प्रत्येक राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य, राज्य कार्यकारी परिषद से परामर्श के बाद, पात्र आवेदकों में से केंद्रीय सलाहकार परिषद द्वारा दो-तिहाई मत से चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य सलाहकार परिषद के पहले सदस्य छह, चार और दो वर्ष के क्रमिक कार्यकालों के लिए, यथासंभव तीन बराबर भागों में, सार्वजनिक लॉटरी द्वारा तय करके नियुक्त होते हैं; 21 तक पहुँचने के लिए बाद में जोड़े गए सदस्य लॉटरी द्वारा उन कार्यकाल समूहों में रखे जाते हैं जिनमें सबसे कम सदस्य हों। अनुच्छेद 29 के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद ही उनकी नियुक्ति का अनुसमर्थन करने वाला निकाय है।
6. कार्यकाल समाप्त होने से पहले रिक्त हुई सीट उसी प्रकार उस कार्यकाल की शेष अवधि के लिए भरी जाती है।
7. कोई भी व्यक्ति जीवनकाल में सलाहकार परिषदों में तीन से अधिक कार्यकाल सेवा नहीं कर सकता। खंड 1 या 5 के अधीन दो या चार वर्ष का पहला कार्यकाल एक कार्यकाल गिना जाता है; खंड 6 के अधीन भरे गए कार्यकाल की शेष अवधि, यदि तीन वर्ष से कम हो, तो नहीं गिनी जाती। कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक सलाहकार परिषद में सेवा नहीं कर सकता।
8. प्रत्येक सलाहकार परिषद अपने सदस्यों में से दो वर्ष के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुनती है।

अनुच्छेद 24. कार्य ।

1. प्रत्येक सलाहकार परिषद अपने स्तर पर नीति, रणनीति और सार्वजनिक मामलों पर पार्टी को सलाह देती है ।
2. प्रत्येक राज्य सलाहकार परिषद अनुच्छेद 25 के अधीन यह प्रमाणित करती है कि उस राज्य के कौन से सदस्य कार्यकारी सदस्य बन सकते हैं और कौन से कार्यकारी सदस्य उस राज्य के किसी भी लोक सभा, विधान सभा या स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र की प्राइमरी में भाग ले सकते हैं ।
3. केंद्रीय सलाहकार परिषद अनुच्छेद 25 के अधीन राष्ट्रीय पद और राज्य सभा के उम्मीदवारों की, तथा ऐसे किसी भी व्यक्ति की पात्रता प्रमाणित करती है जिसका आवेदन एक से अधिक राज्यों से संबंधित हो ।
4. केंद्रीय सलाहकार परिषद प्रति वर्ष प्रत्येक राज्य सलाहकार परिषद के कम से कम 10% प्रमाणनों के यादृच्छिक नमूने की लेखापरीक्षा करेगी और अपने निष्कर्ष प्रकाशित करेगी, ताकि सभी राज्यों में मानदंड एक समान रूप से लागू हों ।
5. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 25 में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, सलाहकार परिषद की भूमिका केवल सलाहकारी है, और उसका कोई भी संकल्प किसी कार्यकारी परिषद या सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है ।

अनुच्छेद 25. वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रमाणन ।

1. कार्यकारी सदस्य के रूप में प्रवेश, या किसी प्राइमरी में भाग लेने की अनुमति, के लिए आवेदन अनुसूची I द्वारा अपेक्षित शपथपूर्वक घोषणा और दस्तावेजों सहित निर्वाचन प्राधिकरण को किया जाएगा ।
2. निर्वाचन प्राधिकरण का सचिवालय प्रत्येक दस्तावेज का सार्वजनिक अभिलेख (न्यायालय अभिलेख, आयकर विवरणी, निर्वाचक नामावली और पार्टी के अपने अभिलेखों सहित) से सत्यापन करेगा और सलाहकार परिषद के समक्ष एक सत्यापन प्रतिवेदन रखेगा, जिसमें अनुसूची I के प्रत्येक मानदंड के लिए बताया जाएगा कि साक्ष्य के अनुसार वह पूरा होता है या नहीं ।
3. सलाहकार परिषद सत्यापन प्रतिवेदन पर, मानदंड-दर-मानदंड, निर्णय लेगी । प्रत्येक आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार सलाहकार परिषद के पास रहता है । वह किसी ऐसे आवेदक को प्रमाणित नहीं करेगी जो कोई भी मानदंड पूरा न करता हो । सभी मानदंड पूरे करने वाले आवेदक को वह केवल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से, आवेदक के आचरण या अभिलेख पर आधारित लिखित कारणों सहित, अस्वीकार कर सकती है; ये कारण आवेदक को दिए जाएंगे और, व्यक्तिगत डेटा के बिना, वार्षिक प्रतिवेदन में संक्षेप में दिए जाएंगे ।
4. परिषद आवेदक का साक्षात्कार ले सकती है । कोई व्यक्तिगत सिफारिश, दान, या आवेदक की लोकप्रियता, किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा या चुनावी संभावनाओं का आकलन निर्णय का भाग नहीं होगा ।
5. निर्णयों के लिए परिषद के आधे सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है और वे बहुमत से लिए जाते हैं । प्रत्येक निर्णय में प्रत्येक मानदंड के लिए, आधारित साक्ष्य सहित, “पूरा” या “पूरा नहीं” दर्ज किया जाएगा ।
6. आवेदक से व्यक्तिगत, व्यावसायिक या पारिवारिक संबंध रखने वाला परिषद सदस्य स्वयं को अलग रखेगा ।
7. परिषद पूर्ण सत्यापन प्रतिवेदन मिलने के 21 दिनों के भीतर निर्णय लेगी । यदि वह ऐसा नहीं करती, तो आवेदक केंद्रीय सलाहकार परिषद से (या केंद्रीय सलाहकार परिषद के मामले में उसके अध्यक्ष से) अनुरोध कर सकता है कि वह आगे 14 दिनों के भीतर निर्णय करवाए । परिषद के निर्णय के बिना कोई आवेदक प्रमाणित नहीं होता ।

8. अस्वीकृत आवेदक को 7 दिनों के भीतर मानदंड-दर-मानदंड लिखित निर्णय मिलता है; वह असफल मानदंड पूरा होने पर पुनः आवेदन कर सकता है, और अनुच्छेद 45 के अधीन मध्यस्थता अधिकरण में अपील कर सकता है।
9. सलाहकार परिषद दावेदारों का प्रस्ताव, नामांकन या जोड़ नहीं कर सकती, न उन्हें क्रम दे सकती है, न किसी अन्य प्रकार से प्राइमरी के परिणाम को प्रभावित कर सकती है।
10. प्रत्येक सलाहकार परिषद प्राप्त, प्रमाणित और अस्वीकृत आवेदनों का, प्रत्येक अस्वीकृति में असफल मानदंड सहित, वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगी।

अनुच्छेद 26. सलाहकार परिषद सदस्यों पर प्रतिबंध। किसी भी सलाहकार परिषद के सदस्य:

1. पार्टी के नाम पर संसद, राज्य विधानमंडलों, स्थानीय निकायों और राज्य सभा सहित कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे;
2. कार्यकारी सदस्य नहीं बनेंगे, कोई पार्टी पद धारण नहीं करेंगे, न आंतरिक पार्टी चुनाव लड़ेंगे;
3. पार्टी प्राइमरी के माध्यम से उम्मीदवारी नहीं चाहेंगे, न किसी प्राइमरी या आंतरिक चुनाव में मत देंगे; और
4. धार्मिक हैसियत से पार्टी या उसके उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगे।

अनुच्छेद 27. प्रकटीकरण और हित-संघर्ष। प्रत्येक सलाहकार परिषद सदस्य नियुक्ति पर और प्रति वर्ष अपने व्यावसायिक हितों, निदेशक पदों और पार्टी को दिए गए दानों की सार्वजनिक घोषणा करेगा, और अपने स्वयं के व्यवसाय, परिवार या सहयोगियों से संबंधित किसी भी सलाह या निर्णय से स्वयं को अलग रखेगा।

अनुच्छेद 28. स्तरों के बीच आवागमन।

1. कोई कार्यकारी सदस्य सभी पार्टी पदों, कार्यकारी सदस्यता और उम्मीदवारियों से त्यागपत्र देने के बाद, और 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि के बाद, सलाहकार परिषद में नियुक्त किया जा सकता है।
2. जिसने किसी भी सलाहकार परिषद में सेवा की है, वह कभी कार्यकारी सदस्य या पार्टी उम्मीदवार नहीं बनेगा।
3. जो व्यक्ति पार्टी के उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ने के लिए सलाहकार परिषद से त्यागपत्र देता है, उसे किसी भी स्तर पर पार्टी में पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

अनुच्छेद 29. पद से हटाना। सलाहकार परिषद के किसी सदस्य को, मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष सुनवाई के बाद, उसकी नियुक्ति का अनुसमर्थन करने वाले निकाय के दो-तिहाई मत से उचित कारण पर हटाया जा सकता है।

भाग V: उम्मीदवार चयन और प्राइमरी

अनुच्छेद 30. प्राइमरी अनिवार्य। पार्टी जिस भी लोक सभा, विधान सभा और नगर निगम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ती है, वहाँ उसका उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत पात्र सदस्यों की प्राइमरी द्वारा चुना जाएगा। अनुच्छेद 34 को छोड़कर कोई अन्य विधि अनुमत नहीं है।

अनुच्छेद 31. क्रम। प्रत्येक प्राइमरी इस क्रम में होती है:

1. निर्वाचन प्राधिकरण प्राइमरी और उसकी समय-सारणी अधिसूचित करता है, और उसी तिथि को प्राइमरी की मतदाता सूची बंद हो जाती है।

2. कार्यकारी सदस्य अद्यतन घोषणाओं और अनुसूची I के भाग ख द्वारा अपेक्षित समर्थक हस्ताक्षरों सहित प्राइमरी में भाग लेने के लिए आवेदन करते हैं।
3. राज्य सलाहकार परिषद अनुच्छेद 25 के अधीन पात्रता प्रमाणित करती है; मध्यस्थता अधिकरण में किसी भी अपील का निर्णय 10 दिनों के भीतर होता है।
4. निर्वाचन प्राधिकरण प्रमाणित दावेदारों की सूची और उनकी घोषणाएँ पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।
5. दावेदार अनुच्छेद 33 की व्यय सीमा के भीतर प्रचार करते हैं और अनुच्छेद 32क के अधीन ऑनलाइन बहस में भाग लेते हैं।
6. पात्र सदस्य अनुच्छेद 32 और 32ख के अधीन ऑनलाइन मत देते हैं। यदि किसी दावेदार को 50% से अधिक मत नहीं मिलते, तो शीर्ष दो दावेदारों के बीच दूसरी बहस होती है और दूसरा चरण होता है।

अनुच्छेद 32. मतदान और दूसरा चरण।

1. सदस्य गुप्त मतदान द्वारा ऑनलाइन एक दावेदार को मत देते हैं।
2. जिस दावेदार को वैध मतों के 50% से अधिक मत मिलते हैं, वह पार्टी का उम्मीदवार होता है।
3. यदि किसी दावेदार को 50% से अधिक मत नहीं मिलते, तो सबसे अधिक मत पाने वाले दो दावेदार दूसरे चरण में जाते हैं, जो 10 दिन बाद, अनुच्छेद 32क के अधीन उनके बीच दूसरी बहस के पश्चात होता है। दूसरे चरण में अधिक मत पाने वाला दावेदार पार्टी का उम्मीदवार होता है।
4. दूसरे चरण में बराबरी होने पर 3 दिनों के भीतर एक और चरण होता है और, फिर भी बराबरी रहने पर, निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक रूप से लॉटरी निकाली जाती है।
5. यदि केवल एक प्रमाणित दावेदार बचता है, तो सदस्य पुष्टि मतदान करते हैं। यदि 50% से अधिक विरोध में मत देते हैं, तो नए आवेदनों के लिए प्राइमरी फिर से खोली जाती है।

अनुच्छेद 32क. ऑनलाइन बहस।

1. प्रत्येक प्राइमरी के पहले चरण से पहले, निर्वाचन प्राधिकरण सभी प्रमाणित दावेदारों के बीच कम से कम एक सीधी ऑनलाइन बहस आयोजित करेगा। दूसरे चरण से पहले, वह शेष दो दावेदारों के बीच एक और बहस आयोजित करेगा।
2. प्रत्येक बहस का संचालक उस सलाहकार परिषद द्वारा चुना जाता है जिसने दावेदारों को प्रमाणित किया: अपने राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए राज्य सलाहकार परिषद, और राष्ट्रीय पद के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद। संचालक न तो पार्टी का सदस्य होगा, न किसी दावेदार से जुड़ा होगा; वह, उदाहरण के लिए, पत्रकार, शिक्षाविद या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। परिषद बहस से कम से कम 7 दिन पहले अपनी पसंद की घोषणा करेगी।
3. संचालक प्रत्येक दावेदार को समान समय देगा, निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित बहस नियमों का पालन करेगा, और सदस्यों द्वारा भेजे गए प्रश्न पूछ सकता है।
4. प्रत्येक बहस का सीधा प्रसारण होगा, उसे रिकॉर्ड करके पार्टी की वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेज़ी और, किसी राज्य के लिए, उसकी प्रमुख भाषा में प्रकाशित किया जाएगा।
5. भाग लेना अनिवार्य है। जो दावेदार निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा स्वीकार्य कारण के बिना बहस में अनुपस्थित रहता है, वह उस प्राइमरी से अयोग्य हो जाता है।

अनुच्छेद 32ख. ऑनलाइन चुनाव।

1. सभी प्राइमरी और आंतरिक चुनाव निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा एक सुरक्षित प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन कराए जाएंगे, जो प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करे, प्रत्येक पात्र सदस्य को एक मत दे, प्रत्येक मतपत्र को गुप्त रखे और लेखापरीक्षा योग्य अभिलेख रखे।

2. प्रत्येक चुनाव से पहले प्रणाली की एक स्वतंत्र सुरक्षा लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी, और परिणाम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान प्रतिशत सहित प्रकाशित किए जाएंगे।
3. मतदान कम से कम 48 घंटे खुला रहेगा। निर्वाचन प्राधिकरण ऐसे सहायता केंद्र उपलब्ध कराएगा जहाँ इंटरनेट सुविधा से वंचित सदस्य गुप्त रूप से मत दे सकें।
4. मतदान खुला रहने तक सदस्य जितनी बार चाहें अपना मत बदल सकते हैं; केवल अंतिम मत गिना जाता है।
5. प्रत्येक सदस्य को एक गोपनीय रसीद मिलती है, जिससे वह जाँच सकता है कि उसका मत जैसा डाला गया वैसा ही दर्ज हुआ, किंतु किसी अन्य को यह पता नहीं चलता कि उसने किसे मत दिया।
6. किसी ऑनलाइन चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष ले जाया जा सकता है।

अनुच्छेद 33. प्रचार आचरण। प्रत्येक दावेदार का प्राइमरी व्यय उस चुनाव में उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग (या राज्य निर्वाचन आयोग) द्वारा निर्धारित व्यय सीमा के दसवें भाग तक सीमित है, और रसीदों सहित निर्वाचन प्राधिकरण को प्रतिवेदित किया जाएगा। दावेदार सदस्यों को कोई प्रलोभन नहीं देंगे, और धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मत नहीं माँगेंगे। मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष सिद्ध होने पर इस अनुच्छेद का उल्लंघन दावेदार के परिणाम को शून्य कर देता है।

अनुच्छेद 34. रिक्तियाँ और आपात स्थितियाँ। यदि नामांकन की अंतिम तिथि से पहले प्राइमरी नहीं हो सकती, या चुने गए उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है, वह नाम वापस ले लेता है या अयोग्य हो जाता है, तो राज्य कार्यकारी परिषद गुप्त मतदान द्वारा उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रमाणित दावेदारों में से, और उनके न होने पर उस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 25 के अधीन प्रमाणित कार्यकारी सदस्यों में से, उम्मीदवार चुनेगी।

अनुच्छेद 35. राज्य सभा और विधान परिषद के उम्मीदवार। राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों के लिए पार्टी के उम्मीदवार संबंधित राज्य की राज्य कार्यकारी परिषद के गुप्त मतदान द्वारा, अनुच्छेद 24(3) के अधीन केंद्रीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रमाणित कार्यकारी सदस्यों में से चुने जाएंगे।

अनुच्छेद 36. उम्मीदवारों का प्राधिकार (प्ररूप क और ख)। निर्वाचन प्रतीक आदेश के अधीन प्ररूप क और ख पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी उन्हें प्राइमरी के विजेता को, या अनुच्छेद 34 या 35 के अधीन चुने गए व्यक्ति को जारी करेगा, किसी अन्य को नहीं। इस विषय में उस पदाधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं है। ऐसा न करना या इससे इनकार करना इस संविधान का उल्लंघन है और इसे मध्यस्थता अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

अनुच्छेद 37. टिकटों की बिक्री निषिद्ध। कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, अनुच्छेद 25 के अधीन प्रमाणन, दावेदार के रूप में नामांकन, या प्ररूप क और ख जारी करने के लिए कोई धन, दान, उपहार या अन्य प्रतिफल न माँगेगा, न देगा, न चुकाएगा, न स्वीकार करेगा। इस संविधान के अधीन किसी भी आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 10क के अधीन अंशदान इन प्रयोजनों के लिए प्रतिफल नहीं हैं और प्रमाणन, नामांकन या उम्मीदवारी का कोई अधिकार नहीं देते। इस अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाला कोई भी दावेदार या उम्मीदवार अयोग्य है और उसकी उम्मीदवारी शून्य है, और ऐसा करने वाला कोई भी सदस्य निष्कासित किया जाएगा। प्रत्येक दावेदार और प्राधिकृत पदाधिकारी शपथपूर्वक घोषणा करेगा कि ऐसा कोई प्रतिफल न दिया गया, न लिया गया।

अनुच्छेद 38. पराजित दावेदार। प्राइमरी हारने वाला दावेदार उस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ेगा। ऐसा करने पर सभी स्तरों पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

भाग V-क: सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार-निरोध

अनुच्छेद 38क. संपत्ति की घोषणा।

1. प्रत्येक दावेदार, पार्टी का प्रत्येक उम्मीदवार और पार्टी का प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि अपने, अपने जीवनसाथी, अपने आश्रितों और अपने नियंत्रण वाले किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब या संस्था द्वारा भारत और विदेश में धारित सभी आस्तियों और दायित्वों की, अपनी आय के स्रोतों और पिछले पाँच वर्षों की आयकर विवरणियों सहित, शपथपूर्वक घोषणा दाखिल करेगा।
2. निर्वाचन प्राधिकरण प्रत्येक ऐसी घोषणा प्राइमरी से पहले पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
3. प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि पद पर रहते हुए प्रति वर्ष और पद छोड़ने पर अद्यतन घोषणा दाखिल करेगा।
4. मिथ्या, अपूर्ण या विलंबित घोषणा स्वयं अनुच्छेद 38ग के अधीन निष्कासन का आधार है।

अनुच्छेद 38ख. सत्यनिष्ठा आयोग।

1. तीन सदस्यों का एक स्वतंत्र सत्यनिष्ठा आयोग घोषणाओं की जाँच करेगा, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संपत्ति की लेखापरीक्षा करेगा, शिकायतें प्राप्त करेगा और किसी भी सदस्य के भ्रष्टाचार की जाँच करेगा।
2. कम से कम एक सदस्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, और कम से कम एक 15 वर्ष के अनुभव वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट या फ़ारेंसिक लेखापरीक्षक होगा। सदस्य कोई अन्य पार्टी पद धारण नहीं करेंगे और कार्यकारी सदस्य या सलाहकार परिषद सदस्य नहीं होंगे।
3. सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई मत से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं और केवल सिद्ध कदाचार पर हटाए जा सकते हैं।
4. आयोग किसी भी व्यक्ति से, दस्तावेजों से समर्थित अनाम शिकायतों सहित, शिकायतें स्वीकार करेगा और व्हिसल-ब्लोअरों की पहचान गुप्त रखेगा। सद्भावपूर्वक शिकायत करने के लिए किसी सदस्य को दंडित नहीं किया जाएगा।
5. आयोग प्रति वर्ष प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि की घोषणाओं की लेखापरीक्षा करेगा, और प्राप्त शिकायतों, की गई जाँचों और निष्कर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा।

अनुच्छेद 38ग. निष्कासन के आधार। यदि सत्यनिष्ठा आयोग अनुच्छेद 38घ के अधीन जाँच के बाद पाता है कि किसी सदस्य ने:

1. अनुच्छेद 38क के अधीन मिथ्या, अपूर्ण या छिपाई गई घोषणा की है;
2. ऐसी आस्तियाँ रखी हैं जो घोषित वैध आय को ध्यान में रखने के बाद उस आय से 10% से अधिक हैं, और जिनका वह संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता;
3. रिश्वत या कोई अवैध परितोषण माँगा, स्वीकार किया, प्रस्तावित किया या दिया है, या निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद या सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है;
4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि पाई है, या न्यायालय द्वारा उस पर आरोप विरचित किए गए हैं; या
5. अनुच्छेद 37 का उल्लंघन किया है,

तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जाएगा।

अनुच्छेद 38घ. प्रक्रिया।

1. आयोग सदस्य को आरोप और साक्ष्य की लिखित सूचना देगा, और सुनवाई का अवसर देगा।
2. जहाँ न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हों या आयोग को प्रथमदृष्टया मामला दिखे, वहाँ आयोग जाँच लंबित रहने तक सदस्य को सभी पार्टी अधिकारों से निलंबित कर सकता है।
3. आयोग अपने समक्ष दस्तावेज़ी और अन्य साक्ष्य के आधार पर, अधिसंभाव्यता की प्रबलता के मानक पर, 60 दिनों के भीतर प्रतिवेदन देगा।
4. सदस्य 15 दिनों के भीतर मध्यस्थता अधिकरण में अपील कर सकता है, और अधिकरण 30 दिनों के भीतर निर्णय करेगा।
5. प्रत्येक निष्कर्ष प्रकाशित किया जाएगा।

अनुच्छेद 38ड. दावेदारों और उम्मीदवारों के लिए परिणाम। अनुच्छेद 38ग के अधीन निष्कासित सदस्य सभी स्तरों से हटा दिया जाता है और उसे कभी पुनः प्रवेश नहीं दिया जा सकता। दावेदार का प्रमाणन वापस ले लिया जाता है, और जहाँ पार्टी उसे पहले ही अपना उम्मीदवार प्राधिकृत कर चुकी हो, वहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी, कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, उस प्राधिकार को वापस लेगा या प्रतिस्थापित करेगा।

अनुच्छेद 38च. निर्वाचित प्रतिनिधि।

1. प्ररूप क और ख प्राप्त करने से पहले, प्रत्येक उम्मीदवार एक सार्वजनिक वचनपत्र पर हस्ताक्षर करेगा कि पद पर रहते हुए अनुच्छेद 38ग के अधीन निष्कासित होने पर वह अपनी सीट से त्यागपत्र दे देगा।
2. यदि कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अनुच्छेद 38ग के अधीन भ्रष्ट पाया जाता है, तो उसे पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, और पार्टी उसे पद से हटवाने के लिए हर विधिसम्मत कदम उठाएगी, जिसमें सम्मिलित हैं:
 1. साक्ष्य पुलिस, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, लोकपाल या लोकायुक्त को भेजना, और अभियोजन की पैरवी करना;
 2. जहाँ भ्रष्टाचार उसके चुनाव से संबंधित हो, वहाँ चुनाव याचिका दायर करना या उसका समर्थन करना;
 3. जहाँ दोषसिद्धि उसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन निरर्हित करती हो, वहाँ उसकी निरर्हिता की माँग करना;
 4. सार्वजनिक रूप से उससे अपना वचन निभाने और त्यागपत्र देने की माँग करना; और
 5. संबंधित सदन में निंदा प्रस्ताव लाना या उसका समर्थन करना।
3. पार्टी इस अनुच्छेद के अधीन उठाए गए कदम और उनका परिणाम प्रकाशित करेगी।

भाग V-ख: घोषित नेतृत्व और मंत्रिस्तरीय मानक

अनुच्छेद 38छ. नेता की सदैव घोषणा। पार्टी लोक सभा या किसी राज्य विधान सभा का आम चुनाव, पहले यह सार्वजनिक रूप से घोषित किए बिना कभी नहीं लड़ेगी कि उसका नेतृत्व कौन करेगा:

1. उस लोक सभा चुनाव के लिए जिसमें पार्टी कम से कम 272 सीटों पर चुनाव लड़ती है, वह व्यक्ति जिसे पार्टी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तावित करेगी; कम सीटों पर लड़ने की दशा में, वह इसके बजाय लोक सभा में अपने दल के नेता का नाम घोषित करेगी; और
2. विधान सभा चुनाव के लिए, वह व्यक्ति जिसे पार्टी उस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित करेगी।

यह घोषणा मतदान की संभावित तिथि से कम से कम छह महीने पहले, या मध्यावधि चुनाव की घोषणा के 30 दिनों के भीतर, की जाएगी।

अनुच्छेद 38ज. घोषित नेता का चयन।

1. प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अनुच्छेद 12 के अधीन सभी पात्र सदस्यों द्वारा, और मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उस राज्य के पात्र सदस्यों द्वारा, अनुच्छेद 32क के अधीन बहसों के बाद, अनुच्छेद 32 और 32ख के अधीन गुप्त ऑनलाइन मतदान से चुना जाता है।
2. उम्मीदवार बनने के लिए व्यक्ति का कार्यकारी सदस्य होना, केंद्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अनुसूची IV में नेता की योग्यताएँ पूरी करने के लिए प्रमाणित होना, और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (प्रधानमंत्री के लिए) या राज्य कार्यकारी परिषद (मुख्यमंत्री के लिए) के कम से कम 10% सदस्यों द्वारा नामित होना आवश्यक है।
3. संबंधित सदन में पार्टी के सदस्य घोषित नेता को अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे, और उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करेंगे।
4. कार्यकाल के दौरान पद रिक्त होने पर 90 दिनों के भीतर इस अनुच्छेद के अधीन नया नेता चुना जाता है; तब तक विधायक दल गुप्त मतदान से अंतरिम नेता चुन सकता है।

अनुच्छेद 38झ. चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की घोषणा। घोषित नेता के साथ, और मतदान से कम से कम तीन महीने पहले, पार्टी सार्वजनिक रूप से उन व्यक्तियों के नाम घोषित करेगी जिन्हें वह सरकार बनाने या उसमें शामिल होने पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्त करेगी:

1. गृह;
2. वित्त;
3. रक्षा;
4. विदेश;
5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण;
6. शिक्षा;
7. विधि और न्याय; और
8. कोई अन्य विभाग जिसे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (या, किसी राज्य के लिए, राज्य कार्यकारी परिषद) संकल्प द्वारा जोड़े।

विधान सभा चुनावों पर भी यही, इन विभागों के राज्य समकक्षों के साथ, लागू होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए घोषित विभाग वे होंगे जो दिल्ली सरकार की शक्तियों के भीतर हैं, जिनमें वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि और न्याय, शहरी विकास, बिजली और जल, तथा परिवहन सम्मिलित हैं, और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 239कक में मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा के भीतर होगा।

अनुच्छेद 38अ. मंत्रिस्तरीय योग्यताएँ।

1. अनुच्छेद 38झ के अधीन घोषित प्रत्येक व्यक्ति, अनुच्छेद 25 की प्रक्रिया के अधीन केंद्रीय सलाहकार परिषद (या, राज्य सरकार के लिए, राज्य सलाहकार परिषद) द्वारा प्रमाणित रूप में, उस विभाग के लिए अनुसूची IV की योग्यताएँ पूरी करेगा।
2. घोषित प्रत्येक व्यक्ति अनुसूची I के भाग क के मानदंड, मानदंड 1 (एक वर्ष की सशुल्क सदस्यता) और 9 (सेवा घंटे) को छोड़कर, भी पूरे करेगा, और अनुच्छेद 38क के अधीन संपत्ति की घोषणा दाखिल करेगा।

3. अनुच्छेद 28 के अनुरूप, किसी सलाहकार परिषद के सदस्य का नाम घोषित नहीं किया जा सकता।
4. घोषित नेता नाम प्रस्तावित करता है; राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (या राज्य कार्यकारी परिषद) बहुमत से उनका अनुमोदन करती है। जहाँ अनुसूची IV में कोई वरीयता दी गई है, वहाँ नेता योग्य व्यक्तियों में से उसे वरीयता देगा जो उसे पूरा करता हो।

अनुच्छेद 38ट. विधानमंडल में प्रवेश। अनुच्छेद 38झ के अधीन घोषित व्यक्ति जो पहले से विधानमंडल का सदस्य नहीं है, पार्टी प्राइमरी के माध्यम से चुनाव लड़ सकता है, अनुच्छेद 35 के अधीन राज्य सभा या विधान परिषद के लिए चुना जा सकता है, या नियुक्त होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(5) और 164(4) द्वारा अनुमत छह महीनों के भीतर निर्वाचित हो सकता है।

अनुच्छेद 38ठ. परिवर्तन और गठबंधन।

1. घोषित व्यक्ति को केवल उन्हीं योग्यताओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से, कारण प्रकाशित करते हुए, बदला जा सकता है।
2. गठबंधन सरकार में, पार्टी अपने पास के किसी भी विभाग में केवल अनुसूची IV को पूरा करने वाले व्यक्तियों को नामित करेगी, और अनुच्छेद 38झ में सूचीबद्ध पदों के लिए अपने सहयोगियों से भी इन्हीं मानकों पर सहमति चाहेगी।
3. जो मंत्री योग्यताएँ पूरी करना बंद कर देता है, या भाग V-क के अधीन निष्कासित होता है, उससे त्यागपत्र देने को कहा जाएगा, और पार्टी उस मंत्री से अपना समर्थन वापस ले लेगी।

भाग VI: पदाधिकारी और आंतरिक चुनाव

अनुच्छेद 39. राष्ट्रीय पदाधिकारी। पार्टी में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष, एक महासचिव और एक कोषाध्यक्ष होंगे, जो सभी कार्यकारी सदस्य होंगे।

1. अध्यक्ष अनुच्छेद 12 के अधीन सभी पात्र सदस्यों द्वारा, अनुच्छेद 32क के अधीन बहसों के बाद, अनुच्छेद 32 और 32ख के अधीन गुप्त ऑनलाइन मतदान से चुना जाता है। उम्मीदवार बनने के लिए व्यक्ति का केंद्रीय सलाहकार परिषद द्वारा प्रमाणित होना और पार्टी के निर्वाचित विधायकों के कम से कम 15% द्वारा, या जब तक पार्टी के 20 विधायक न हों तब तक राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के कम से कम 10% द्वारा, नामित होना आवश्यक है।
2. उपाध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा गुप्त मतदान से चुने जाते हैं।

अनुच्छेद 40. राज्य और ज़िला पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य में एक राज्य अध्यक्ष, एक राज्य महासचिव और एक राज्य कोषाध्यक्ष होगा। राज्य अध्यक्ष उस राज्य के अनुच्छेद 12 के अधीन पात्र सदस्यों द्वारा, और अन्य राज्य कार्यकारी परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ज़िला और निर्वाचन क्षेत्र इकाइयाँ अनुच्छेद 17 के अधीन बनाए गए नियमों का पालन करेंगी।

अनुच्छेद 41. कार्यकाल। सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, एक ही पद पर अधिकतम लगातार दो कार्यकाल। निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, आंतरिक चुनाव कम से कम प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार होंगे।

अनुच्छेद 42. प्राधिकृत पदाधिकारी। अनुच्छेद 36 के अधीन रहते हुए, महासचिव प्ररूप क और ख सहित निर्वाचन आयोग के साथ पत्राचार के लिए पार्टी का प्राधिकृत पदाधिकारी है। पार्टी अपने महासचिव के नाम से वाद ला सकती है और उसके नाम से उस पर वाद लाया जा सकता है।

अनुच्छेद 43. निर्वाचन आयोग को सूचना। पार्टी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क(9) की अपेक्षा के अनुसार, अपने नाम, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारियों या इस संविधान में किसी भी परिवर्तन की सूचना निर्वाचन आयोग को देगी।

भाग VI-क: सदस्य लोकतंत्र और जवाबदेही

अनुच्छेद 43क. गठबंधनों पर सदस्यों का अनुमोदन। कोई भी चुनाव-पूर्व गठबंधन, सीट-बँटवारे की व्यवस्था, चुनाव-पश्चात गठबंधन, या किसी अन्य दल के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने या उसका समर्थन करने का निर्णय तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक अनुच्छेद 32ख के अधीन ऑनलाइन मतदान में मत देने वाले पात्र सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका अनुमोदन न हो: राष्ट्रीय निर्णय के लिए सभी पात्र सदस्य, और राज्य संबंधी निर्णय के लिए उस राज्य के पात्र सदस्य। जहाँ सरकार के शपथ ग्रहण से पहले मतदान का समय न हो, वहाँ राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (या राज्य कार्यकारी परिषद) अस्थायी अनुमोदन दे सकती है, जो 30 दिनों के भीतर सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन न होने पर समाप्त हो जाता है; यदि सदस्य अस्वीकार करते हैं, तो पार्टी उस व्यवस्था से हट जाएगी।

अनुच्छेद 43ख. सदस्य पहल।

1. सभी पात्र सदस्यों के कम से कम 5% (या, राज्य संबंधी विषय के लिए, उस राज्य के 5%) पात्र सदस्य, निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा सत्यापित ऑनलाइन याचिका द्वारा, किसी नीतिगत प्रस्ताव या इस संविधान के संशोधन पर सदस्यों का ऑनलाइन मतदान करवा सकते हैं।
2. मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित नीतिगत प्रस्ताव पार्टी की नीति बन जाता है और, अनुच्छेद 43ट के अधीन लागत-आकलन के अधीन रहते हुए, अगले घोषणापत्र में सम्मिलित किया जाएगा।
3. पहल द्वारा प्रस्तावित संशोधन तब प्रभावी होता है जब पात्र सदस्यों के कम से कम 20% मतदान के साथ, मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई द्वारा उसका अनुमोदन हो; अनुच्छेद 49 के अधीन संरक्षित किसी अनुच्छेद के संशोधन के लिए मत देने वाले सदस्यों के तीन-चौथाई की आवश्यकता है।
4. निर्वाचन प्राधिकरण वैध याचिका मिलने के 60 दिनों के भीतर मतदान कराएगा।

अनुच्छेद 43ग. घोषणापत्र सदस्य लिखते हैं।

1. प्रत्येक सदस्य किसी भी समय पार्टी के घोषणापत्र के लिए ऑनलाइन सुझाव दे सकता है। कम से कम 500 पात्र सदस्यों द्वारा समर्थित सुझाव वार्षिक ऑनलाइन नीति मतदान में जाता है।
2. प्रत्येक आम चुनाव से पहले, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद (या राज्य कार्यकारी परिषद) सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों से बना घोषणापत्र का प्रारूप प्रकाशित करेगी, उसे कम से कम 30 दिनों तक सदस्यों की टिप्पणियों के लिए खुला रखेगी, और पात्र सदस्यों के ऑनलाइन मतदान के बाद ही उसे अंगीकार करेगी।

अनुच्छेद 43घ. पदाधिकारियों को वापस बुलाना। यदि किसी पद के लिए मत देने के पात्र सदस्यों में से कम से कम 20% निर्वाचन प्राधिकरण को याचिका देते हैं, तो उस पद के धारक को 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन विश्वास मत का सामना करना होगा। यदि मत देने वालों का बहुमत विश्वास वापस ले लेता है, तो पद रिक्त हो जाता है और 60 दिनों के भीतर नया चुनाव होता है। किसी पदाधिकारी पर किसी भी 12 महीनों में एक से अधिक बार वापसी मतदान नहीं हो सकता।

अनुच्छेद 43ड. पार्टी पद और सार्वजनिक पद का पृथक्करण। कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संघ या राज्य का मंत्री और राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष का पद धारण नहीं कर सकता। मंत्री बनने वाला पदाधिकारी 30 दिनों के भीतर पार्टी पद से त्यागपत्र देगा।

अनुच्छेद 43च. स्वतः पुनर्नामांकन नहीं। पार्टी का प्रत्येक वर्तमान संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य या पार्षद, जो पुनः चुनाव चाहता है, किसी अन्य दावेदार के समान शर्तों पर पार्टी प्राइमरी लड़ेगा।

अनुच्छेद 43छ. कार्यकाल की सीमा। कोई भी व्यक्ति एक ही सीट के लिए लगातार तीन कार्यकाल से अधिक पार्टी का उम्मीदवार नहीं होगा, और न ही सदन के लगातार तीन कार्यकाल से अधिक पार्टी द्वारा एक ही मंत्रालय के लिए नामित किया जाएगा।

अनुच्छेद 43ज. व्हिप का सीमित प्रयोग।

1. पार्टी किसी विधानमंडल में अपने सदस्यों को केवल विश्वास या अविश्वास प्रस्तावों, बजट और धन विधेयकों, और सदस्यों द्वारा अनुमोदित घोषणापत्र की प्रतिबद्धताओं को लागू करने वाले उपायों पर ही व्हिप जारी करेगी।
2. अन्य सभी विषयों पर, पार्टी के विधायक अनुच्छेद 4क के अनुरूप अपने विवेक और अंतरात्मा के अनुसार मत देते हैं।
3. व्हिप जारी करने का निर्णय विधायक दल के बहुमत द्वारा लिया जाएगा और कारणों सहित प्रकाशित किया जाएगा।

अनुच्छेद 43झ. महिलाओं का प्रतिनिधित्व। प्रत्येक कार्यकारी परिषद प्रतिनिधिमंडल, प्रत्येक सलाहकार परिषद, पदाधिकारियों की प्रत्येक टीम, निर्वाचन प्राधिकरण, सत्यनिष्ठा आयोग और मध्यस्थता अधिकरण के कम से कम एक-तिहाई सदस्य महिलाएँ होंगी। निर्वाचन प्राधिकरण महिला दावेदारों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित और सहायता करेगा, और यदि किसी आम चुनाव में पार्टी के एक-तिहाई से कम उम्मीदवार महिलाएँ हों, तो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद इसके कारण और उठाए जाने वाले कदम प्रकाशित करेगी।

अनुच्छेद 43ञ. युवा शाखा। पार्टी की एक युवा शाखा होगी, जो 18 से 35 वर्ष आयु के सदस्यों के लिए खुली होगी। युवा शाखा अनुच्छेद 32ख के अधीन ऑनलाइन मतदान द्वारा अपना अध्यक्ष और कार्यकारिणी चुनती है, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद और प्रत्येक राज्य कार्यकारी परिषद में उसकी दो मताधिकार-प्राप्त सीटें हैं, और प्रत्येक घोषणापत्र पर उससे परामर्श किया जाएगा।

अनुच्छेद 43ट. घोषणापत्र का स्वतंत्र लागत-आकलन। किसी घोषणापत्र के अंगीकार से पहले, उसकी प्रत्येक प्रतिबद्धता का लागत-आकलन केंद्रीय सलाहकार परिषद द्वारा नियुक्त, पार्टी के सदस्य न होने वाले तीन अर्थशास्त्रियों या लोक-वित्त विशेषज्ञों के एक स्वतंत्र पैनल द्वारा किया जाएगा। लागत-आकलन, और प्रत्येक प्रतिबद्धता का खर्च कैसे पूरा होगा, घोषणापत्र के साथ प्रकाशित किया जाएगा। लागत-आकलन के बिना कोई प्रतिबद्धता सम्मिलित नहीं की जा सकती।

अनुच्छेद 43ठ. दानों का शीघ्र प्रकटीकरण। पार्टी को मिला प्रत्येक दान, और किसी दावेदार को प्राइमरी अभियान के लिए मिला प्रत्येक दान, कानून द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों के अतिरिक्त, प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा: ₹2,000 से अधिक के दान दाता के नाम और राशि सहित, और छोटे दान कुल योग के रूप में।

अनुच्छेद 43ड. पद छोड़ने के बाद प्रतिबंध। पद छोड़ने के बाद दो वर्षों तक, पार्टी की ओर से मंत्री या विधायक रहा कोई भी व्यक्ति किसी निजी हित के लिए सरकार के समक्ष पैरवी नहीं करेगा, और न ही किसी ऐसी कंपनी में रोज़गार, निदेशक पद या परामर्श स्वीकार करेगा जिसके मामलों का उसने पद पर रहते हुए विनियमन या निर्णय किया हो। उल्लंघन अनुच्छेद 48 के अधीन निष्कासन का आधार है।

अनुच्छेद 43द. अभिलेखों का प्रकाशन। राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद, प्रत्येक राज्य कार्यकारी परिषद, प्रत्येक सलाहकार परिषद और निर्वाचन प्राधिकरण के निर्णय, कार्यवृत्त और दर्ज मत 14 दिनों के भीतर पार्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँगे, केवल आवेदकों और सदस्यों का व्यक्तिगत डेटा छोड़कर।

अनुच्छेद 43ण. सदस्य शिकायत निवारण अधिकारी (ओम्बड्समैन)। एक स्वतंत्र सदस्य ओम्बड्समैन, जो पार्टी का सदस्य नहीं होगा, राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई मत से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। ओम्बड्समैन सदस्यता, डेटा प्रबंधन और देरी सहित पार्टी प्रशासन के विरुद्ध सदस्यों की शिकायतों की जाँच करता है; उपचार की सिफारिश करता है; मामलों को मध्यस्थता अधिकरण को भेज सकता है; और वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता है।

अनुच्छेद 43त. मतदाताओं को जवाबदेही। पार्टी का प्रत्येक संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और पाषद अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम प्रत्येक तीन महीने में एक बार, सभी निवासियों के लिए खुली और ऑनलाइन प्रसारित, सार्वजनिक सभा करेगा, और उपस्थिति, पूछे गए प्रश्नों, दिए गए मतों, क्षेत्र विकास निधि के उपयोग और घोषणापत्र की प्रतिबद्धताओं की प्रगति पर एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करेगा।

भाग VII: निर्वाचन प्राधिकरण और मध्यस्थता अधिकरण

अनुच्छेद 44. निर्वाचन प्राधिकरण। तीन सदस्यों का एक स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण, एक सचिवालय सहित, सदस्यों का रजिस्टर रखता है, अनुच्छेद 25 के अधीन आवेदनों का सत्यापन करता है, सभी प्राइमरी और आंतरिक चुनाव कराता है, व्यय सीमाएँ लागू करता है और परिणाम घोषित करता है। इसके सदस्य कार्यकारी सदस्य या सलाहकार परिषद सदस्य नहीं होंगे, और न ही अपने द्वारा संचालित कोई चुनाव लड़ेंगे। वे राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई मत से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं और केवल सिद्ध कदाचार पर हटाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 45. मध्यस्थता अधिकरण। तीन सदस्यों का एक मध्यस्थता अधिकरण सुनवाई करता है:

1. अनुच्छेद 25 के अधीन सलाहकार परिषद के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की: जहाँ वह पाता है कि कोई मानदंड गलत लागू हुआ या प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, वहाँ वह आवेदन को नए निर्णय के लिए परिषद को लौटाएगा, और स्वयं किसी आवेदक को प्रमाणित नहीं करेगा;
2. प्राइमरी और आंतरिक चुनावों से संबंधित विवादों की;
3. अनुशासनात्मक अपीलों की; और
4. इस शिकायत की कि किसी पार्टी निकाय ने इस संविधान के विपरीत कार्य किया है।

कम से कम एक सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता होगा। सदस्य कोई अन्य पार्टी पद धारण नहीं करेंगे, और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई मत से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं, जिन्हें केवल सिद्ध कदाचार पर हटाया जा सकता है।

अनुच्छेद 46. प्रक्रिया। अधिकरण प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर देगा, 30 दिनों के भीतर (या प्राइमरी के दौरान 10 दिनों के भीतर) निर्णय करेगा, और कारण लिखित रूप में दर्ज करेगा। इसके निर्णय, कानून में उपलब्ध किसी भी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पार्टी के भीतर अंतिम होते हैं।

भाग VIII: वित्त, अनुशासन, संशोधन और विघटन

अनुच्छेद 47. वित्त। कोषाध्यक्ष:

1. पार्टी की निधियाँ पार्टी के नाम के बैंक खातों में रखेगा, जिनका संचालन कम से कम दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा होगा;
2. किसी भी व्यक्ति से ₹2,000 से अधिक का नकद दान, और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में परिभाषित कोई विदेशी अंशदान, स्वीकार नहीं करेगा;
3. ₹20,000 से अधिक के प्रत्येक दान की सूचना प्रति वर्ष निर्वाचन आयोग को देगा (प्ररूप 24क);
4. लेखों की प्रति वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेखापरीक्षा कराएगा और आयकर अधिनियम की धारा 13क के अधीन छूट हेतु अपेक्षानुसार उन्हें दाखिल करेगा; और
5. लेखापरीक्षित लेख और ₹20,000 से अधिक के दाताओं की सूची सदस्यों के लिए प्रकाशित करेगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के वित्तीय वर्ष के लेख भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के राजनीतिक दलों हेतु मार्गदर्शन के अनुरूप रखेगा, और अंशदान प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेख निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसे दाखिल करेगा।

अनुच्छेद 47क. सार्वजनिक लेखे।

1. पार्टी को प्राप्त प्रत्येक दान, किसी भी राशि का, प्राप्त के 7 दिनों के भीतर उसकी तिथि और राशि सहित, और अनुच्छेद 43ठ के अनुसार दाता के नाम सहित, पार्टी की वेबसाइट पर दिखाया जाएगा।
2. पार्टी प्रति माह अपनी वेबसाइट पर प्राप्त सभी निधियों (अंशदान, शुल्क और दान), सभी व्यय, और पार्टी के प्रत्येक बैंक खाते की अंतिम शेष राशि का विवरण प्रकाशित करेगी।
3. ₹10,000 से अधिक का प्रत्येक व्यय उसकी तिथि, राशि, प्रयोजन और प्राप्तकर्ता सहित दिखाया जाएगा।
4. लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, निर्वाचन आयोग को दाखिल अंशदान प्रतिवेदन और लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दाखिल होते ही वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे।
5. प्रत्येक राज्य इकाई इन्हीं शर्तों पर अपने लेखे प्रकाशित करेगी।

अनुच्छेद 48. अनुशासन। इस संविधान या आचार संहिता के उल्लंघन पर, आरोप की लिखित सूचना और संबंधित कार्यकारी परिषद की अनुशासन समिति के समक्ष सुनवाई के बाद, किसी सदस्य को निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। प्रत्येक अनुशासनात्मक निर्णय के विरुद्ध मध्यस्थता अधिकरण में अपील की जा सकती है।

अनुच्छेद 49. संशोधन। इस संविधान में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई मत से, निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराए गए मतदान में मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसमर्थन सहित, संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3, 25, 26, 28, 37 और 38क से 38च तथा अनुसूचियाँ I और II दोनों चरणों में केवल तीन-चौथाई मत से संशोधित की जा सकती हैं, और अनुसूची I या II का कोई संशोधन पहले से किए गए आवेदन पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 43ख के अधीन सदस्य पहले द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। प्रत्येक संशोधन की सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाएगी।

अनुच्छेद 50. विलय और विघटन। पार्टी किसी अन्य दल में केवल राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के तीन-चौथाई मत और सदस्यों के दो-तिहाई मत से ही विलय या विघटित हो सकती है। विघटन पर, ऋण चुकाने के बाद, शेष आस्तियाँ राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किसी पंजीकृत धर्मार्थ निकाय को जाएंगी, किसी व्यक्ति को नहीं।

अनुच्छेद 51. संस्थापक प्रावधान। पहले आंतरिक चुनावों तक, जो पंजीकरण के 18 महीनों के भीतर होंगे, पंजीकरण आवेदन में नामित संस्थापक पदाधिकारी पद पर रहेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के कार्य करेंगे। पहली केंद्रीय सलाहकार परिषद अनुच्छेद 23(1) के अधीन संस्थापक द्वारा चुनी जाएगी। निर्वाचन प्राधिकरण, मध्यस्थता अधिकरण, सत्यनिष्ठा आयोग और सदस्य ओम्बड्समैन के पहले सदस्य पंजीकरण के तीन महीनों के भीतर संस्थापक पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और निर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की पहली बैठक में उनका अनुसमर्थन होगा। पहले दो वर्षों में, संस्थापक सदस्यों के लिए अनुसूची I की एक वर्ष की सशुल्क सदस्यता की शर्त घटाकर 6 महीने की जा सकती है। पार्टी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से शुरू होगी और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद द्वारा तय चरणों में, एक-एक करके अन्य राज्यों में विस्तार करेगी; तब तक केंद्रीय सलाहकार परिषद और दिल्ली राज्य कार्यकारी परिषद दिल्ली के लिए राज्य निकायों के कार्य करेंगी। केवल दिल्ली के पहले नगर निगम चुनाव के लिए, संस्थापक पदाधिकारियों के दो-तिहाई मत से अनुच्छेद 12 की मतदान पात्रता अवधि घटाकर 6 महीने की जा सकती है।

अनुच्छेद 52. व्याख्या और भाषा। यह संविधान अंग्रेज़ी और हिंदी में अंगीकृत किया गया है; दोनों पाठों में अंतर होने पर अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा। इसकी व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न मध्यस्थता अधिकरण द्वारा तय किया जाता है। यदि कोई प्रावधान अमान्य ठहराया जाता है, तो शेष प्रभावी रहते हैं।

पार्टी की संस्थापक बैठक, [स्थान] में [तिथि] को, अंगीकृत।

अध्यक्ष: _____ महासचिव: _____

अनुसूची I: पात्रता मानदंड

प्रत्येक मानदंड दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर पूरा होता है या नहीं होता। कोई भी मानदंड पूरा न करने वाले आवेदक को प्रमाणित नहीं किया जाएगा; सभी मानदंड पूरे करने वाले आवेदक को भी सलाहकार परिषद अनुच्छेद 25(3) के अधीन अस्वीकार कर सकती है।

भाग क: कार्यकारी सदस्य के रूप में प्रवेश

1. **सदस्यता:** आवेदन से ठीक पहले कम से कम एक वर्ष तक लगातार सशुल्क सदस्य, अद्यतन शुल्क सहित।
2. **नागरिकता और निवास:** भारत में सामान्यतः निवास करने वाला भारत का नागरिक, जिसका नाम संबंधित राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में हो; प्रवासी निर्वाचक के रूप में पंजीकृत न हो, और भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक न हो।
3. **प्रशिक्षण:** इस संविधान, पार्टी के उद्देश्यों और आचार संहिता पर पार्टी का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया हो, और उसकी लिखित परीक्षा कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण की हो।
4. **शपथपूर्वक घोषणा:** निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए विहित प्ररूप (प्ररूप 26 या उसका उत्तरवर्ती) में आस्तियों, दायित्वों, आय, शैक्षिक योग्यताओं और आपराधिक पृष्ठभूमि की शपथपूर्वक घोषणा, जहाँ कानूनन आवश्यक हो वहाँ पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियों सहित, दाखिल की हो।
5. **दोषसिद्धि नहीं:** किसी निरर्हकारी अपराध के लिए दोषसिद्ध न हो।
6. **कोई गंभीर लंबित आरोप नहीं:** किसी निरर्हकारी अपराध के लिए किसी न्यायालय ने आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित न किए हों जो लंबित हों। केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत से यह मानदंड असफल नहीं होता।

7. **कोई विधिक निरर्हता नहीं:** भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 या 191, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अधीन निरर्हित न हो।
8. **जानबूझकर चूक नहीं:** भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अधीन किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित न हो, और ₹1,00,000 से अधिक की कोई अंतिम, अदत्त कर माँग न हो।
9. **सेवा:** पिछले वर्ष में कम से कम 50 घंटे की पार्टी या सामुदायिक सेवा, जो पार्टी के सेवा रजिस्टर में दर्ज और ज़िला इकाई द्वारा सत्यापित हो।
10. **स्तर पृथक्करण:** कभी किसी सलाहकार परिषद में सेवा न की हो।
11. **सत्य प्रकटीकरण:** पिछले छह वर्षों में मध्यस्थता अधिकरण द्वारा मिथ्या या छिपाए गए प्रकटीकरण का कोई निष्कर्ष न हो।

भाग ख: प्राइमरी में भाग लेने की अनुमति

1. प्राइमरी अधिसूचित होने से कम से कम 6 महीने पहले से अच्छी स्थिति वाला कार्यकारी सदस्य।
2. आवेदन से पहले 30 दिनों के भीतर अद्यतन घोषणाओं के आधार पर, भाग क का प्रत्येक मानदंड पूरा करता रहे।
3. भारत के संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन, न्यूनतम आयु सहित, उस सीट की योग्यताएँ पूरी करे।
4. उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जिसमें निर्वाचन क्षेत्र स्थित है।
5. नामांकन उस प्राइमरी में मत देने के पात्र कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षरों से समर्थित हो, जिनका सत्यापन निर्वाचन प्राधिकरण करे।
6. अनुच्छेद 37 के अधीन यह शपथपूर्वक घोषणा कि नामांकन के लिए कोई प्रतिफल न दिया गया है न देने का वादा किया गया है, और अनुच्छेद 38 के अधीन संपत्ति की घोषणा दाखिल की हो, और भाग V-क के अधीन निलंबित या निष्कासित न हो।
7. ऐसा पराजित दावेदार न हो जिसने पिछले छह वर्षों में पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव लड़ा हो।

भाग ग: राष्ट्रीय पद और राज्य सभा

राष्ट्रीय पद और राज्य सभा या विधान परिषद के उम्मीदवार भाग क और ख के प्रत्येक मानदंड (भाग ख के मानदंड 4 और 5 को छोड़कर) को पूरा करेंगे और, राष्ट्रीय पद के लिए, कम से कम 2 वर्ष तक कार्यकारी सदस्य रहे हों।

अनुसूची II: निरर्हकारी अपराध

1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन कोई भी अपराध।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(1) या 8(2) में सूचीबद्ध कोई भी अपराध।
3. भारतीय न्याय संहिता, 2023 (या भारतीय दंड संहिता, 1860 के संगत प्रावधानों) के अधीन चुनाव संबंधी अपराध।
4. बलात्संग, लैंगिक हमला, दहेज मृत्यु, या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन कोई भी अपराध।
5. हत्या, हत्या का प्रयास, फिरोती के लिए अपहरण, या उद्घापन।
6. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन कोई भी अपराध।

- मानव तस्करी, या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन तस्करी संबंधी अपराध।
- पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय कोई अन्य अपराध।

अनुसूची III: आचार संहिता

प्रत्येक सदस्य:

- भारत के संविधान और इस संविधान को बनाए रखेगा;
- न रिश्त देगा न लेगा, और रिश्त की किसी भी माँग की सूचना निर्वाचन प्राधिकरण को देगा;
- पार्टी पद, प्रमाणन या टिकट के लिए कोई भुगतान, उपहार या अनुग्रह न माँगेगा न प्रस्तावित करेगा;
- धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर घृणा या हिंसा नहीं भड़काएगा;
- प्रत्येक प्राइमरी और आंतरिक चुनाव के परिणाम का सम्मान करेगा, और अन्य दलों की नीतियों की आलोचना करेगा, उनके सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं;
- जिस भी पार्टी विषय में भाग ले, उसमें किसी भी हित-संघर्ष की घोषणा करेगा; और
- पार्टी की निधियों और संपत्ति का उपयोग केवल पार्टी प्रयोजनों के लिए, रसीदों सहित, करेगा।

अनुसूची IV: नेता और मंत्रियों की योग्यताएँ

प्रत्येक योग्यता दस्तावेज़ी साक्ष्य के आधार पर पूरी होती है या नहीं होती। “वरीयता” वाले बिंदु योग्य व्यक्तियों में से नेता के चयन का मार्गदर्शन करते हैं, किंतु पात्रता की शर्तें नहीं हैं।

पद	आवश्यक योग्यताएँ	वरीयता
प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि; कार्यकारी सदस्य के रूप में या वरिष्ठ व्यावसायिक, प्रशासनिक या सार्वजनिक नेतृत्व में कम से कम 10 वर्ष	स्नातकोत्तर उपाधि
शिक्षा	भारत या विदेश के किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि; शिक्षण, अनुसंधान या शिक्षा प्रशासन में कम से कम 10 वर्ष	किसी अग्रणी विदेशी विश्वविद्यालय की उपाधि; डॉक्टरेट
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या किसी राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकृत योग्य चिकित्सक (एमबीबीएस या समकक्ष); नैदानिक चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य या स्वास्थ्य प्रशासन में कम से कम 10 वर्ष	स्नातकोत्तर चिकित्सा या लोक-स्वास्थ्य योग्यता
रक्षा	थल सेना, नौसेना या वायु सेना	उच्चतर पद; संयुक्त या

पद	आवश्यक योग्यताएँ	वरीयता
वित्त	का कर्नल (थल सेना), कैप्टन (नौसेना) या ग्रुप कैप्टन (वायु सेना) या उससे ऊपर के पद का सेवानिवृत्त अधिकारी, जो कम से कम दो वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ हो कम से कम 15 वर्ष का वरिष्ठ नेतृत्व, जिसमें ₹10,000 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार वाली किसी कंपनी या समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के रूप में कम से कम 5 वर्ष हों; और एक व्यावसायिक योग्यता (चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सचिव) या अर्थशास्त्र, वित्त, वाणिज्य या व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि	रणनीतिक कमान का अनुभव किसी सूचीबद्ध कंपनी या बड़े सार्वजनिक उपक्रम का अनुभव; पद पर रहते हुए सभी हिस्सेदारियों का पूर्ण विनिवेश या ब्लाइंड ट्रस्ट
गृह	पुलिस महानिदेशक या उससे ऊपर के पद का सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या भारत सरकार के सचिव या उससे ऊपर के पद का सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी	आंतरिक सुरक्षा या आपराधिक-न्याय सुधार का अनुभव
विदेश	सचिव या राजदूत या उससे ऊपर के पद का सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा अधिकारी, या अंतरराष्ट्रीय मामलों, कूटनीति या वैश्विक व्यवसाय में कम से कम 15 वर्ष	किसी प्रमुख विदेशी भाषा में प्रवीणता
विधि और न्याय	विधि की उपाधि और अधिवक्ता, न्यायाधीश या विधि शिक्षक के रूप में कम से कम 15 वर्ष	वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदनाम, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा

राज्य सरकारों के लिए, यही योग्यताएँ संगत राज्य विभागों (गृह, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि) पर लागू होती हैं; रक्षा और विदेश इसमें सम्मिलित नहीं हैं।